मध्यप्रदेश में प्रारंभ होंगे नए वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटरः मुख्यमंत्री

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र और वन्यजीवों की विविधता से संपन्न राज्य है। भारत में सबसे अधिक बाघ (टाइगर) मध्यप्रदेश की धरती पर देखने को मिलते हैं। तेंदुआ (लेपर्ड) और गिद्ध (वल्चर) की संख्या भी मध्यप्रदेश में सबसे अधिक है। प्रदेश के अलग-अलग वन क्षेत्रों में मगरमच्छ और घड़ियालों का बसेरा है।

प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण, जंगलों की रक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर स्थापित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने बुधवार को गुजरात रवाना होने के पहले मीडिया में जारी एक संदेश में यह विचार रखे। डॉ. यादव ने कहा कि अब वन्यजीव प्रेमियों के लिए मध्यप्रदेश में किंग कोबरा भी लेकर आए हैं। चीतों को पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर वन क्षेत्र में छोड़कर एक नया नेशनल पार्क विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक दो नए टाइगर नेशनल पार्क बनने और चीतों के साथ-साथ दूसरे वन्य जीवों की संख्या बढ़ने से संभाग स्तर पर रेस्क्यू सेंटर की आवश्यकता महसूस हो रही है। इन सेंटर्स की स्थापना के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक केवल एक रेस्क्यू सेंटर राजधानी भोपाल स्थित वन विहार में है। यहां प्रदेशभर से घायल और बीमार वन्यजीवों को इलाज के लिए लाया जाता है, लेकिन उनके अनुकूल वातावरण में बदलाव हो जाने के कारण कई बार परेशानियां आती हैं। वन्यप्राणियों की जीवन रक्षा और उनके जीवन में सुखद बदलाव लाने के लिए संभाग स्तर पर रेस्क्यू सेंटर शुरू करने का प्रयास है।

जू की संख्या बढ़ेगी

राज्य सरकार प्रदेश में चिड़ियाघरों अर्थात प्राणी उद्यान (जू) की संख्या में भी वृद्धि करने जा रही है। बजट में दो प्राणी उद्यान की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। गुजरात में देश का सर्वश्रेष्ठ जू एवं रेस्क्यू सेंटर है। आपने बताया कि गुजरात की अध्ययन यात्रा में जामनगर में वन्यजीवों की देखरेख के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। साथ ही वन्यजीवों का आदान-प्रदान कर उनके जीवन रक्षा की संभावनाएं भी तलाशेंगे। डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के कई विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में वेटनरी कोर्स और वेटनरी अस्पताल शुरू कर पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। निकट भविष्य में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। वन संपदा और वन्यजीवों के संरक्षण का भी व्यापक अभियान प्रदेश में चल रहा है।

श्रमिक परिवारों के खातों में कल संबल योजना की राशि होगी अंतरित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संबल योजना अंतर्गत, अनुग्रह सहायता के 6821 प्रकरणों में 150 करोड़ रूपये सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। शुक्रवार को जबलपुर के बरगी में होने वाले इस कार्यक्रम में श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

अनुग्रह सहायता के 6821 प्रकरणों में 150 करोड़ रुपए का होगा अंतरण

प्रदेश में संबल योजना, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। योजना अन्तर्गत प्रारंभ से अब तक 1 करोड़ 76 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। पंजीयन प्रक्रिया निरंतर जारी है। योजना में अनुग्रह सहायता अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये प्रदान किये जाते हैं। स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये एवं आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपये तथा अंत्येष्टि सहायता के लिए 5 हजार रूपये प्रदान किये जाते हैं। संबल योजना में जहाँ एक ओर महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता के लिये 16 हजार रुपये दिये जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर श्रमिकों के बच्चों को महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना में उच्च शिक्षा के लिये सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भारत सरकार के नीति आयोग की पहल पर प्रदेश के गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स को भी संबल योजना में सम्मिलित किया जाकर इनका पंजीयन प्रारम्भ किया गया है। इन्हें भी संबल योजना के अंतर्गत समस्त लाभ प्रदान किये जा रहे हैं। संबल हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी प्राप्त होती है, जिससे वे केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर रहे हैं।

सिकल सेल मिशन के कार्य मानवता की सेवा का माध्यमः पटेल

भोपाल(काप्र)।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन के लिए संवेदनशीलता, सहानुभूति के साथ रोग उन्मूलन की प्रतिबद्धता जरूरी है। कार्य का भाव लक्ष्य को समय सीमा से पूर्व पूरा करने का होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सिकल सेल मिशन के कार्य मानवता की सेवा के माध्यम है। ईश्वरीय कृपा के भागी होने का यह बड़ा अवसर है। श्री पटेल राजभवन में सिकल सेल मिशन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राजेन्द्र शुक्ल, आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग के द्वारा सिकल सेल उपचार, प्रबंधन और नियंत्रण प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। उनको बताया गया कि मिशन के अंतर्गत 19 जून से 3 जुलाई तक समस्त ग्राम पंचायतों, एकलव्य आवासीय स्कूलों एवं छात्रावासों में मेगा शिविर आयोजित होंगे। अधिक से अधिक स्क्रीनिंग जांच की जाएगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से लेकर जिला चिकित्सालयों में पीओसी किट के द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रतिदिन स्क्रीनिंग जांच का डेटा पोर्टल में दर्ज होगा। जेनेटिक काउंसलिंग की जाएगी। जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्रदान किए जाएंगे। ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर चिन्हित सिकल सेल रोगियों के लिए शिविर लगेंगे। उन्हें विशेषज्ञों की परामर्श सेवायें उपलब्ध कराई जाएगी। सिकल सेल रोगियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड प्रदान कर पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।

आयुष विभाग द्वारा बताया गया कि विश्व सिकल सेल दिवस के तारतम्य में जनजातीय बहुल 20 जिलों में संचालित 78 आयुष औषधालयों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। सिकल सेल उपचार में सहायक आयुर्वेद दवाओं की किट का वितरण होगा। रोग उपचार में सहायक स्थानीय वनस्पति के संरक्षण, संवर्धन के प्रति जन जागरूकता के कार्य होंगे। सिकल सेल एनीमिया प्रभावित प्रत्येक ग्राम में जनजागृति के लिए प्रभात फेरी, योगाभ्यास, ग्राम-सभा आदि के आयोजन किए जाएंगे। बैठक में जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खांडेकर, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव, राज्यपाल के अपर सचिव उमाशंकर भार्गव, सचिव जनजातीय प्रकोष्ठ श्रीमती जमुना भिड़े, संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सुश्री सलोनी सिडाना, आयुक्त आयुष संजय मिश्रा उपस्थित थे।

अमृत हरित कार्यशाला रवीन्द्र भवन में कल

भोपाल(काप्र)।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा शुक्रवार 13 जून को प्रातः 8:30 बजे राजधानी के रवीन्द्र भवन में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला अमृत हरित अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में हरित क्षेत्र के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों और पहलों का प्रसार करना है।

कार्यशाला में मंत्रीगण, सांसद, विधायक, महापौर, निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जन-प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रत्येक नगर निगम से 6, नगरपालिका परिषद से 4 और नगर परिषद से 2 प्रतिभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गयी है। कार्यशाला के दौरान कृषि और उद्यानिकी से संबंधित उत्पादों एवं यंत्रों की प्रदर्शनी के साथ ही नर्सरी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जायेगा। कार्यशाला में विभिन्न संस्थानों जैसे इफ्को एवं भारतीय प्रबंध संस्थान के विषय-विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जायेगी। कार्यशाला में स्थानीय वृक्ष प्रजातियों की विशेषताएँ एवं संरक्षण, जैव-विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, बगीचों के लिये तकनीक एवं उपकरण की आवश्यकताएँ, वृक्षारोपण और पौध-रोपण से संबंधित अधिनियमों का विश्लेषण तथा वृक्षारोपण उपरांत समुचित प्रबंधन विषय पर चर्चा की जायेगी।

हरित क्षेत्र बढ़ाने की रणनीतियाँ

कार्यशाला में दिव्यांग पार्क, होशंगाबाद एवं उज्जैन की सफलता की कहानियों को भी साझा किया जायेगा। इन कहानियों पर आधारित फिल्म का विशेष प्रस्तुतिकरण किया जायेगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण समस्त नगरीय निकायों में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किया जायेगा, जिससे राज्य के सभी निकाय इस अभियान से जुड़ सकें। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे के निर्देशन में अपर आयुक्त कैलाश वानखेड़े ने सभी नगरीय निकायों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये हैं। इसके साथ ही पौधरोपण कार्य में संलग्न शासकीय और अशासकीय संगठनों के प्रतिनिधि भी कार्यशाला में भाग लेंगे।

हरित क्षेत्र से जुड़े विषय-विशेषज्ञों के होंगे व्याख्यान

नेहरू-गांधी परिवार को यथार्थ बोलने वाले कांग्रेस में बर्दाश्त नहीं: सारंग

भोपाल (काप्र)।

सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी से छह वर्ष के लिए निष्कासित किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि लक्ष्मण सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि नेहरू परिवार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बंधुआ मजदूर बनाकर रखना चाहता है।

लक्ष्मण सिंह हमेशा यथार्थ की बातें करते हैं, इसलिए वे नेहरू-गांधी परिवार को बर्दाश्त नहीं हैं। लक्ष्मण सिंह पर कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि नेहरू-गांधी परिवार को सत्य बताने वाला, पार्टी के अंदर यथार्थ बोलने वाला, कांग्रेस के जीजाजी के खिलाफ बोलने वाला कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकता। जिस प्रकार से लक्ष्मण सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने कार्रवाई की है वह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक होने के साथ दुर्भाग्यपूर्ण भी है। श्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेहरू-गांधी परिवार के चंगुल में ऐसी फंसी है कि उसे सच सुनने की आदत नहीं है। श्री सिंह ने जो कहा वह यथार्थ है। यदि कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवाद स्थापित करने की मानसिकता हो तो उन्हें लक्ष्मण सिंह के बयान पर गौर करना चाहिए, न कि कार्रवाई। कांग्रेस ने एक बार फिर यह सिद्ध दिया है कि नेहरू परिवार के खिलाफ या नेहरू परिवार को सत्य बताने की जो भी कोशिश करेगा वह कांग्रेस में नहीं रहेगा। श्री सारंग ने कहा कि लक्ष्मण सिंह ने तो ठीक ही कहा था कि कांग्रेस के हालात ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रही है। आप सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर यदि प्रश्न चिन्ह लगाते हो तो यह देशद्रोह है। राहुल गांधी जैसे नौसिखिए जिन्हें राजनीति की एबीसीसी नहीं आती, वह यदि लक्ष्मण सिंह जैसे अनुभवी राजनेता के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर कांग्रेस का क्या होगा यह सबको पता है।

सिपरी साफ्टवेयर की बारीकियां सीखने आज आएगा महाराष्ट्र का दल

भोपाल। जल गंगा संवर्धन अभियान में मनरेगा परिषद द्वारा किए गए नवाचार का अध्ययन करने महाराष्ट्र सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का 9 सदस्यीय दल दो दिवसीय दौरे पर 12 जून को भोपाल आएगा। साथ ही फील्ड में जाकर सिपरी साफ्टवेयर खेत तालाब और अमृत सरोवरों के निर्माण स्थल चयन में किस तरह से काम करता है, दल के सदस्य इसकी बारीकियां सीखेंगे। इसके साथ ही मनरेगा परिषद द्वारा कार्ययोजना को लेकर तैयार किए गए प्लानर ऐप के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस दौरान दल के सदस्य 12 जून को राजधानी एवं 13 जून को रायसेन जिले के सांची विकासखंड का भ्रमण करेंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत बारिश के पानी को बचाने के लिए बनाए जा रहे खेत तालाब, अमृत सरोवर और कूप रिचार्ज पिट का कार्य देखेंगे। महाराष्ट्र सरकार के वाटरशेड विभाग के अति मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलाकर रानादेवी के नेतृत्व में 9 सदस्यों का दल 12 और 13 जून को मध्य प्रदेश प्रवास पर आ रहा है। वे यहां आकर सिपरी सॉफ्टवेयर के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसे कैसे बनाया गया है, इसमें किस-किस तरह के डेटाबेस का उपयोग किया जा रहा है इसका गहन अध्ययन करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इसका उपयोग वे किस तरीके से महाराष्ट्र में प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के कार्यों के लिए कर सकते हैं।

आयातित नेता अभी नहीं बनेंगे कांग्रेस जिलाध्यक्ष

भोपाल (काप्र)।

मध्य प्रदेश कांग्रेस को मजबूत करने के लिए संगठन को नए तरीके से तैयार किया जा रहा है। पार्टी में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जा रहा है। प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान शुभारंभ में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 3 जून को किया था। उसके बाद हुई बैठक के बाद खबर आई थी कि जिला अध्यक्षों के लिए 35 से 45 साल तक की उम्र रखी गई है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे खारिज कर दिया है। उन्होंने बुधवार को पीसीसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिला अध्यक्ष के लिए 45 साल अधिकता उम्र की बात कही जा रही है। लेकिन यह निराधार है जिला अध्यक्षों के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है केवल योग्यता ही पैमाना है। योग्य व्यक्तियों को जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि दूसरे पार्टियों से आने वाले नेताओं को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। कम से कम पार्टी में 5 साल का काम करने का अनुभव होना जरूरी है। बीते करीब 20 सालों से सत्ता से बाहर कांग्रेस अब बदलाव के रास्ते आगे बढ़कर वापसी करना चाह रही है। पार्टी ने अभी से 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन मजबूत करने की रणनीति बनानी शुरू कर दिया है। प्रदेश के सभी जिलों में बनाए जाने वाले जिला अध्यक्ष को लेकर अब मंथन चल रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने साफतौर पर कह दिया है कि भाजपा से आये हुए नेताओं को कम से कम 5 साल पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर गुजारना होगा। जिसके बाद संगठन आगे इस पर फैसला लेगा। यह निर्णय कांग्रेस के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को देखकर लिया गया है, जो पिछले कई सालों से कांग्रेस में सक्रिय रहकर पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 165 ऑब्जर्वर्स को नियुक्ति की है।

श्री पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, जो गरीबों, किसानों और ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए शुरू की गई थीं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। जल जीवन मिशन से लेकर स्वच्छ भारत मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में अरबों रुपये का गबन, फर्जी बिलिंग, और कागजी प्रगति का घिनौना खेल सामने आया है। उन्होने कहा कि मध्यप्रदेश में केंद्र की हर योजना भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। यह भ्रष्टाचार न केवल जनता के विश्वास को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि गरीबों, किसानों और ग्रामीणों के हक को छीन रहा है।

पटवारी बोले-उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं

नगरीय आपदाओं की रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष

भोपाल(काप्र)।

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास संकेत भोंडवे के निर्देश पर वर्षा ऋतु में प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में जल-भराव, बाढ़, जर्जर भवनों के गिरने जैसी संभावित आपदाओं से निपटने के लिए भोपाल में राज्य स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है।

नियंत्रण कक्ष के संचालन एवं समन्वय के लिये एक विशेष दल का गठन किया गया है, जिसमें कार्यपालन यंत्री उपदेश शर्मा, सहायक यंत्री सुनील श्रीवास्तव सहित कुल 8 अधिकारी-कर्मचारी पदस्थ किये गये हैं। यह दल प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में जर्जर एवं क्षतिग्रस्त भवनों को चिन्हित करने और संबंधित नगरीय निकायों के बीच कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। राज्य स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष बाढ़ अथवा जल-भराव की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों के विस्थापन, मूलभूत सुविधाओं जैसी उपलब्धता के लिए समन्वय भी सुनिश्चित करेगा। नियंत्रण कक्ष मौसम कार्यालय से समन्वय कर पूर्व सूचना प्राप्त करेगा तथा संभावित रूप से प्रभावित नगरीय निकायों को अलर्ट भी जारी करेगा।

स्पेशल खबर प्रदेश में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन...

एक पृथ्वी-एक स्वास्थ्य थीम पर आधारित होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

भोपाल(काप्र)।

प्रदेश में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन जिला, विकासखण्ड एवं पंचायत स्तर पर 21 जून को सामूहिक योग कार्याक्रम का वृहद आयोजन किया जायेगा।

इसमें सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों (स्कूल शिक्षा/ उच्च शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा/ आयुष/ नर्सिंग/ पशु चिकित्सा/ कृषि शिक्षा) पॉलिटेक्निक, आईटीआई एवं समस्त शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के छात्रों के अलावा अन्य समस्त शैक्षणिक सस्थानों के विद्यार्थी शामिल होंगे। साथ ही योग संस्थानों, एनसीसी, एनएसएस, पुलिसकर्मियों, विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान, शासकीय सेवकों, स्वयंसेवी संगठन, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संगठन सहित आम नागरिकों की सामूहिक योग कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। प्रदेश के समस्त शासकीय/निजी संस्थाओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होने आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई लिंक पर आयोजक के रूप में पंजीयन कराना होगा। इससे केन्द्र सरकार के स्तर पर प्रदेश में आयोजन की संख्या निर्धारित हो सकेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा योग को वैश्विक पहचान देते हुए वर्ष 2015 में 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। वर्ष 2015 से संपूर्ण विश्व में योग के प्रति उत्साही भागीदारी देखी गई है।

प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी होगा आयोजन

केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस की निर्धारित थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी गई है। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी योग दिवस का आयोजन किया जायेगा। सामूहिक योग प्रदर्शन स्वैच्छिक होगा। प्रदेश की समस्त शासकीय/अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा इसे आवश्यक रूप से आयोजित किया जायेगा। केन्द्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा कॉमन योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) निर्धारित कर सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान किए जाने वाले योगासनों के बारे में अनेक भाषाओं में एवं यू-ट्यूब पर उपलब्ध है। प्रदेश में समय-सारणी अनुसार एक ही समय पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। स्थानीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों का उद्बोधन प्रातः 6 से 6:30 बजे तक राजधानी से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के उद्बोधन का सीधा प्रसारण प्रातः 6.30 से 6:40 बजे तक और विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण प्रातः 6:40 से 7 बजे और योगाभ्यास प्रातः 7 से 7:45 बजे होगा।

प्रत्येक आयोजन स्थल पर पर्याप्त संख्या में योग प्रशिक्षक उपलब्ध कराये जायेंगे। इन्हें देखकर सभी सहभागी योग कर सकेंगे। आयोजन स्थल पर निर्वाध विद्युत प्रवाह, ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेंगी। वर्षा की स्थिति में आयोजन इनडोर किया जा सकता है। सभी जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख पर्यटन स्थलों पर वृहद आयोजन किये जायेंगे। सभी नगर निगम, तहसील, विकासखण्ड, नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रों में एक प्रमुख स्थान पर आयोजन होंगे।

काउंटडाउन का आयोजन भी

इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक दशक पूरा होने पर काउंटडाउन का आयोजन किया जायेगा। इस संबंध में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। योग संगम में 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक उद्यानों में सामूहिक रूप से स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा योगाभ्यास है।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 43/आर-3 स्नेह नगर रोड, गोपालगंज सागर (म.प्र.) - 470001 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन -1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक : डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक : अपूर्व तिवारी। * भोपाल कार्यालय फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. MPHIN/2015/61503, www.naiduniaonline.com